



# बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग - 1

सोमवार, तिथि 06 चैत्र, 1939 (श.)  
27 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या - 17

1.	कृषि विभाग	-	-	01
2.	पंचायती राज विभाग	-	-	03
3.	ग्रामीण कार्य विभाग	-	-	06
4.	भवन निर्माण विभाग	-	-	02
5.	ग्रामीण विकास विभाग	-	-	02
6.	पथ निर्माण विभाग	-	-	03
				<u>कुल योग - 17</u>

### मिनी लैब स्थापित नहीं

अ- 138. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि राज्य में अभी मिट्टी जांच की रफ्तार बहुत धीमी है;
- (ख) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2012 से 19 सितम्बर, 2016 तक मिट्टी जांच के 341001 नमूनों की जांच कर 1771447 स्वायल हेल्थ कार्ड किसानों को दिया गया है, लेकिन लैब स्थापित नहीं किये जाने से राज्य के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कृषि विज्ञान केन्द्र पर एक-एक मिनी लैब स्थापित करने की योजना बनाने एवं किसानों के खेतों की मिट्टी जांच की रफ्तार तेज करने का विचार रखती है, ताकि किसानों को इसका लाभ मिले?

-----

### भवन निर्माण कबतक

192. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाना है। इसी क्रम में पूर्वी चम्पारण जिला के रक्सौल प्रखंड के भेलाही पंचायत में भवन का निर्माण होना है;
- (ख) क्या यह सही है कि भेलाही के पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु अंचलाधिकारी रक्सौल के द्वारा खाता संख्या-8, खेसरा 2418, रकबा 4 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन है, पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण आम सभा से प्रस्तावित जमीन है, पर संवेदक द्वारा बनाना था;
- (ग) क्या यह सही है कि रक्सौल के अंचलाधिकारी द्वारा उक्त खाता सं.-8, खेसरा सं.-2418, रकबा 4 एकड़ पर पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु बार-बार स्मारित किया गया, जिसके बाद संवेदक द्वारा उक्त स्थल पर निर्माण कराने हेतु निविदा का एग्रीमेंट भी किया गया परन्तु आपराधिक तत्व एवं कमिशन हेतु उक्त स्थल पर नहीं बनने दिया जा रहा है;

---

अ- दिनांक 20.03.2017 से स्थगित।

- (घ) क्या यह सही है कि आम सभा एवं अंचलाधिकारी रक्सौल के प्रस्ताव के बिना भेलाही पंचायत की जनभावनाओं एवं पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों की जनभावनाओं के विपरित भेलाही पंचायत जठा अस्पताल-स्टेशन-बाजार-पुलिस स्टेशन है जहां 15 वार्ड स्थित है, वहां बनाकर चुपचाप, प.चम्पारण सीमा स्थित सरेह में जो भेलाही पंचायत से 5 कि.मी. दूरी पर बनाया जा रहा है, जो गलत है;
- (ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भेलाही बाजार स्थित उक्त खाता, खेसरा, रकबा पर पंचायत भवन बनाये तथा गलत स्थान पर निर्माण पर रोक लगाना चाहती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

**पुल निर्माण कबतक**

193. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि गया जिला के डुमरिया प्रखंड अन्तर्गत पंचायत बहुडी में ग्राम पोखरपुर एवं राजवलिया के बीच सोरहर नदी में पुल नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर जनहित में आवागमन सुलभ करने हेतु पुल का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

-----

**योजना से जोड़ना कबतक**

194. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत हर घर नल का जल योजना के लिए पंचायतों के गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में काम कराने के लिए मॉडल इस्टीमेट बनाने की योजना थी;
- (ख) क्या यह सही है कि 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धन राशि से वार्डों के हर घर को नल का जल देने का प्रावधान किया गया है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा प. चम्पारण के नरकटियागंज प्रखंड हेतु मॉडल इस्टीमेट तैयार किया गया है या नहीं, हां तो कुल लागत और कितने वार्डों को इस योजना में जोड़ने की व्यवस्था सरकार कर रही है?

-----

### सड़क का निर्माण कबतक

195. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरूआ प्रखंड के कई ग्रामीण सड़क कच्ची हैं, जिसके कारण प्रखंड के ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;
- (ख) क्या यह सही है कि दिनांक 25.01.2017 को छ: विभिन्न सड़क निर्माण कराने एवं बुनियादी सुविधा मुहैया कराने के लिए विभाग ने धनरूआ प्रखंड में 17.367 किलोमीटर के विरुद्ध 9 करोड़ 41 लाख 21 हजार की राशि आवंटित की है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त वर्णित प्रखंड में कौन-कौन सी छ: सड़कें हैं और उन सड़कों का निर्माण कार्य कबतक शुरू एवं पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?

-----

### पहुंच पथ का निर्माण कबतक

196. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि दरभंगा के बेनीपुर स्थित पोहदी पड़री पथ के कन्हौली घाट तक 6 वर्ष पहले निर्माण कराए गए पुल का पहुंच पथ आज तक नहीं बनाया गया है, जिससे करोड़ों रुपये की लागत से बना पुल बेकार साबित हो रहा है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त पुल विभाग की उदासीनता के कारण लोग नदी में तैरकर गांव जाने को विवश हैं;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा के बेनीपुर स्थित पोहदी पड़री पथ के कन्हौली घाट तक 6 वर्ष पहले निर्माण कराए गए पुल के पहुंच पथ का निर्माण यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

-----

### सड़क का जीर्णोद्धार कबतक

197. श्री नीरज कुमार : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि पटना जिला के दनियावां प्रखंड के नयका रोड से जीवनचक्र-तोप-सरथुआ-खरवैया रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण किया गया था, जिसकी हालत जर्जर है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की अनुरक्षण (मैटेनेंस) की अवधि भी निर्धारित थी लेकिन समय अवधि में सड़क जर्जर हो गयी है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस सड़क का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

-----

### पार्क निर्माण कबतक

198. श्री सूरज नन्दन प्रसाद : क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि पटना शहर के कंकड़बाग स्थित डिफेंस कॉलोनी पार्क में शहीद स्मारक का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 8 वर्ष पूर्व करने के बावजूद इसका निर्माण अबतक नहीं किया गया है;
- (ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसके निर्माण का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

-----

### पुल निर्माण कबतक

199. श्री टुन जी पाण्डेय : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि सीवान जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड के गंभीरपुर पंचायत के नारायणपुर और बैदोली के बीच सोन नदी पर पुल नहीं रहने से हथुआ से तिवेरा रोड का संपर्क बरसात के दिनों में टूट जाता है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी पर पुल नहीं रहने से ग्रामीणों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नारायणपुर और बैदोली के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

### शौचालय निर्माण कबतक

200. श्री कृष्ण कुमार सिंह : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि 'शौचालय निर्माण, घर का सम्मान' के तहत खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2016-17 में 1999 पंचायतों के 41.2 लाख घरों में शौचालयों का निर्माण कराने का लक्ष्य है लेकिन अबतक मात्र 2.7 लाख घरों में ही शौचालयों का निर्माण हो पाया है तथा 38.5 लाख घरों में निर्माण नहीं हो पाया है;
- (ख) क्या यह सही है कि शहरी इलाकों में इस वर्ष 3.3 लाख घरों में शौचालय का निर्माण कराने का लक्ष्य है लेकिन अबतक मात्र 49447 घरों में ही यह सुविधा हो पाई है तथा 280553 घरों में निर्माण नहीं हो पाया है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के 38.5 लाख घरों में तथा शहरी इलाकों के 280553 घरों में शौचालय निर्माण कराकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

-----

### नियुक्त कबतक

201. श्री दिनेश प्रसाद सिंह : क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि जिला परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति के फलस्वरूप अब स्वीकृत बल के विरुद्ध मात्र दस (दस) प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसके कारण कार्य बाधित होता है;
- (ख) क्या यह सही है कि जिला परिषद् द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर विचार किया जाता है तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने की बात कही जाती है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला परिषद् को कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार देना चाहती है, यदि नहीं तो सरकार स्वयं कर्मचारियों की नियुक्ति करके जिला परिषद् को सौंपना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

-----

### पहुंच पथ का निर्माण कबतक

202. श्री विनोद नारायण झा : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि गंगा सेतु का जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होना निर्धारित है;
- (ख) क्या यह सही है कि गंगा पुल के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ होने के पश्चात् पुल पर जाम की समस्या गंभीर हो जायेगी;
- (ग) क्या यह सही है कि निर्माणाधीन दीघा-सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल के पहुंच पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन करा देने से गांधी सेतु पर आवागमन की कठिनाइयों से निजात पाना संभव हो सकेगा;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दीघा-सोनपुर सड़क-सह-रेल पुल के पहुंच पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर आवागमन चालू करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

### सड़क का जीर्णोद्धार कबतक

203. प्रो. संजय कुमार सिंह : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि लखीसराय नगर परिषद् क्षेत्र के कबैया थाना के बगल से लखीसराय बाईपास एवं मकुना टोला होते हुए पचना रोड को जोड़ने वाले सम्पर्क पथ की स्थिति काफी जर्जर है;
- (ख) क्या यह सही है कि किऊल नदी से बालू का उठाव एवं वाहनों के अधिक दबाव से सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है एवं पैदल चलने में भी कठिनाई है तथा हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबैया थाना से बाईपास एवं पचना रोड को जोड़ने वाली सड़क का जीर्णोद्धार कबतक करना चाहती है?

-----

### पथ का निर्माण कबतक

204. श्री राणा गंगेश्वर सिंह : क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के मनियर गाछी से वाजिदपुर सीमान पर अधूरा निर्माण पड़ा है जिससे काफी कठिनाई हो रही है;
- (ख) क्या यह सही है कि कुछ बांध अंश से छोटकी पतलिया एवं पतलिया तथा वाजिदपुर सीमान तक का पथ निर्माण अधूरा पड़ा है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अधूरा पथ का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

-----

### भवन खाली कबतक

205. श्री केदार नाथ पाण्डेय : क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि विधायक आवासन क्षेत्र में पड़ने वाले आवासों को तोड़ने हेतु नीलामी सूचना सं.-6, वर्ष 2014-15 में आमंत्रित नीलामी रेल एस.पी., आवास-रोड नं.-2, बी.सी. पटेल पथ, पटना को तोड़कर मलबा हटाने हेतु मो. अनवर खान, लोदीपुर, पटना को सर्वोच्च बोलीकर्ता के रूप में चुना गया था;
- (ख) क्या यह सही है कि खान द्वारा नीलामी की राशि रु.-125500/- मात्र वर्ष 2014-15 में ही जमा कर दी गई है;
- (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 एवं 2015 में उक्त मकान को तोड़ने हेतु कई पत्र प्रधान सचिव, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को दिए जा चुके हैं परंतु आजतक उक्त मकान खाली नहीं कराया जा सका है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र उक्त मकान को खाली कराकर तोड़ने हेतु आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

-----



**पथ निर्माण कबतक**

206. **श्री हीरा प्रसाद बिन्द** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा अनुमंडल में राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा हिलसा नूरसार हथकट्टा मोड़ से उसमानपुर एन.एच.-30 तक ग्रामीण पथ का निर्माण कार्य सम्पन्न कराया गया है;
- (ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित ग्रामीण पथ, पथ निर्माण विभाग में परिवर्तित होने से ग्रामीण जनता को आवागमन में काफी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खंड 'क' में वर्णित निर्मित पथ को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

**अधिसूचना निर्गत कबतक**

207. **श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता** : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि मोतिहारी जिला के खजुरिया को प्रखंड बनाने की मांग वर्षों से सरकार के समक्ष लंबित है;
- (ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रखंड को अधिसूचित किए जाने के बाद सरकार के प्रशासनिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यों में बहुत सहायता पहुंचेगी क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से सभी मायनों में यह प्रखंड का दर्जा पाने लायक है;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खजुरिया को प्रखंड घोषित करने की अधिसूचना शीघ्र निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

-----

पटना  
दिनांक : 27 मार्च, 2017

**सुनील कुमार पंवार**  
सचिव  
बिहार विधान परिषद्